preparation which will, upon finalisation, be intergrated with the existing draft. This revised document will then be submitted, through due process, for consideration and approval of the National Development Council.

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशियों का जारी किया जाना

1006. **श्री राघव जी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोकसभा और राज्य सभा के उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिनके निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 को पूरी धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ख) उनके लिए वर्ष, 1997-98 की भी पूरी धनराशि अभी तक जारी न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि 1998-99 का अगला वर्ष पहले ही शरू हो चुका है; और

(ग) ये राशियां उन्हें कब तक उनके लिए जारी कर दी जाएंगी।

रेल संसदीय कार्य, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियां कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को ध्यान में रखते हुए दो किश्तों में अवमुक्त की जाती है। तदनुसार वर्ष, 1997-98 के लिए निर्णय लिया गया था कि निधियां उन सांसदों को जारी की जाएंगी जिनके खाते में अस्वीकृत बकाया राशि 50 लाख रुपए से कम हो। इस अनुमोदित मानदंड के अनुसार तथा संबंधित जिला कलेक्टरों से प्राप्त सूचना के आधार पर 790 सांसदों में से 675 सांसद (482 लोकसभा+193 राज्यसभा) तथा 292 सांसद (205 लोकसभा+87 राज्यसभा), निधियों की क्रमशः पहली एवं दूसरी किश्त के अवमोचन के लिए पात्र पाए गए थे। शेष सांसदों को निधियां जारी नहीं कि जा सकी क्योंकि या तो उनके पास अस्वीकृत बकाया राशि 50 लाख रुपए से ऊपर थी या संबंधित जिला कलेक्टरों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) वर्ष, 1997-98 की शेष राशि पात्र सांसदों को वर्ष, 1998-99 के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार जारी की जाएगी।

Cost Overrun of PSUs on Account of Rise in Input Costs

1007. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the cost overrun of PSUs on account of rise in input costs mainly oil, coal and freight traffic?

(b) whether the Govt. had visualised this cost over run before formulating the planning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) The Central Sector projects are approved at estimated costs corresponding to the price level existing in the year of approval. As on December, 1997, 454 projects costing Rs. 20 crores and above, monitored by the Department of Programme Implementation, had a total cost overrun of Rs. 21,063 crores including cost overrun on account of rise in input costs of oil, coal and freight traffic as also other factors with respect to their latest approved cost of Rs. 1,46,168 crores.

(b) The increase in cost during the period of construction due to cost escalation including rise in input costs on account of oil, coal, freight traffic and other factors depending upon the nature of a project is visualised by the project authorities and they are included in the revised cost estimates of projects.

सांसद निधि का जारी किया जाना

1008. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांसद निधि का आबंटन कैलेण्डर वर्ष के आधार पर होता है अथवा वित्तीय वर्ष के आधार पर होता है;

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1997 अथवा वित्तीय वर्ष 1997-98 की एक सौ लाख रुपए की नियत राशि में से अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) शेष राशि कब तक जारी कर दी जाएगी; और

(घ) इस संबंध में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं और इसे नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल, संसदीय कार्य, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से संबंधित निधियों का आबंटन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। एमपीलैड्स संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निधियों का अवमोचन निर्माण कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को देखते हुए दो किश्तों में किया जाता है। तदनुसार वर्ष 1997-98 के लिए यह निर्णय लिया गया था कि जिन संसद सदस्यों के खाते में अस्वीकृत बकाया राशि 50 लाख रुपए से कम हो, उनके लिए निधियां अवमोचित कर दी जाएं। 790 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से 483.5 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 1997-98 के लिए पहली और दूसरी किश्त के रूप में जारी कर दी गई थी। वर्ष 1997-98 के लिए शेष बची हुई राशि उपर्युक्त मानदंड के अनुसार पात्र संसद सदस्यों के नाम अवमुक्त कर दी जाएगी।

Indentification of Family as below poverty lines

1009. SHRIMATI MALTI SHARMA: PROF. RAM KAPSE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present monetary limit for identifying the family as Below Poverty Line, and when this limit was fixed;

(b) whether Government propose to enhance this monetary limit in view of the changed economic conditions;

(c) the proposed limit in terms of annual income for the purpsoe; and

(d) the State-wise details of the families 'below poverty line' during last three years in accordance with the then prevailing monetary limits prescribed for 'Below Poverty Line'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PRALIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) The poverty line at the national level is expressed in terms of monthly per capita consumer expenditure of Rs. 49.09 in rural areas and Rs. 56.64 in urban areas in 1973-74. These are disaggragated into state-specific pvoerty lines on the basis of state-wise price indices and inter-state prcie differential. The pvoerty lines are continuosly updated for change in the price rise. The state-specific pvoerty lines in terms of monthly per capita consumption expenditure in rural and urban areas for the year 1993-94 are given in the Annexure. [*See* Appendix 184, Annexure No. 32]

(d) The Planning Commission estimates the number and percentage of people living below the poverty line in different states and at national level on the basis of quinquennial National Sample Survey (NSS) data on consumer expenditure. The latest estiamtes of state-wise pvoerty are based on the NSS Consumer Expenditure data of 1993-94 (50th Round of NSS). As such, the estiamtes of poverty for the last three years are not available. The state-wise estimates of poverty for the year 1993-94 are enclosed in Annexure-II. [*See* Appendix 184 Annexure No. 32].

Review of 20 Point Economic Programme

1010. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the implementation of the 20 Point Economic Programme in different states;

(b) If so, the details thereof during Eighth Five Year Plan, state-wise; and

(c) the details, of the plan and programme drawn-up in that regard for Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME